जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 58 प्रभात चूरू, बुधवार 25 जून, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

‘पूरा यूक्रेन हमारा है?’

सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकोनॉमिक फोरम के समारोह में पुतिन ने यूक्रेन की अखंडता को चुनौती ही नहीं दी, बल्कि उसे मिटा दिया

- पुतिन ने यह वक्तव्य देने का समय व स्थान बहुत सोच समझकर चुना है। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद, अमेरिकी नेतृत्व में गठित टॉस्क फोर्स का अब विघटन सा हो गया है और विश्व का ध्यान इज़रायल-ईरान युद्ध पर केन्द्रित है। अतः रूस ने मौके का पूरा लाभ लेने का सोचा है, पुराने सोवियत यूनियन का आकार पाने के लिए।
- पुतिन के लिये युद्ध केवल भूमि हथियाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी सभ्यता व ऐतिहासिक पहचान को मजबूत करने के लिए है।
- पुतिन ने यूक्रेन को अपना पड़ोसी नहीं बताया, बल्कि सोवियत साम्राज्य का टूटा हुआ अंग बताया, जिसे पुनः ‘‘मेन बॉडी’’ से जोड़ना है।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जून। युद्ध के अब तक के सबसे भड़काऊ बयानों में से एक में, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच पर अपने मंत्रमुग्ध श्रोताओं के सामने यह घोषणा की: ‘‘पूरा यूक्रेन हमारा है।’’ यह कोई यूं ही दिया गया भड़काऊ बयान नहीं था। यह एक भयंकर संकेत था, रूस की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के औपचारिक रूप से विस्तार का, जिसे ऐतिहासिक नियति के आवरण में छिपाकर पेश किया गया और यह बयान जिस आत्मविश्वास के साथ दिया गया, वह सिहरन पैदा करने वाला था। पुतिन का यह बयान केवल राष्ट्रवादी नारा नहीं था, बल्कि यह विस्तृत रुस के प्रति उनकी गहरी वैचारिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उनका यह यकीन इस गणना पर आधारित है कि वैश्विक स्थिति अब उनके पक्ष में निर्णायक रूप से झुक गई है।

पुतिन ने यह घोषणा करते हुए कि ‘‘रूस और यूक्रेन एक ही राष्ट्र हैं,’’ के साथ साम्राज्यवादी नारा ‘‘जहां एक रूसी सैनिक पैर रखता है, वह हमारा है,’’ दिया, इस प्रकार न केवल यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती दी, बल्कि अपने देशवासियों की नज़रों में यूक्रेन की क्षेत्रीय एकता व अखंडता को मिटा भी दिया। इसके बाद जो तालियों की गड़गड़ाहट हुई, वह कोई स्वाभाविक स्वीकृति नहीं थी; यह एक ऐसे सिस्टम में व्याप्त सहमति थी, जहां पुतिन के शब्द राजनीति शास्त्र बन चुके हैं।

यूएस के नेशनल सिक्योरिटी जर्नल में छपे एक आलेख के अनुसार, शांति वार्ता की जो बची-खुची उम्मीदें थीं, वे अब पूरी तरह से समाप्त हो सकती हैं। तुर्की में चल रही बैक चैनल वार्ता अब नाकाम हो सकती है, क्योंकि मॉस्को अपना रुख कठोर कर रहा है, और कीव, जैसी कि उम्मीद थी, अपनी संप्रभुता से समझौता करने से इनकार करता है। पुतिन ने सार्थक उद्देश्यपूर्ण कूटनीति में शामिल होने से इंकार कर दिया है, हालाँकि पहले उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मिलने के संकेत दिए थे। उनका रुख अब डोनेट्स्क और ज़ापोरिज़्ज़िया में जारी सैन्य हमलों से और कठोर हो गया है।

हालांकि, सबसे ज्यादा जिस बात ने लोगों को चौंका दिया, वह थी पुतिन की अप्रत्यक्ष परमाणु धमकी, कि अगर यूक्रेन द्वारा कथित ‘‘डर्टी बम’’ इस्तेमाल किया जाता है तो। हालांकि ऐसे दावों का आधार नहीं है, लेकिन पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी का वही खेल दोहराया। कीव ने इस आरोप को खारिज करते हुए इसे एक और प्रोपेगेंडा करार दिया, जो सैन्य आक्रमण को सही ठहराने के लिए रूस की पुरानी रणनीति का हिस्सा है।

पुतिन का बयान जितना भड़काऊ है, उसका समय उतना ही रणनीतिक है, ट्रम्प के वाइट हाउस लौटने के बाद, यूक्रेन में अमेरिका की भूमिका नगण्य हो गई है। रॉयटर्स के अनुसार, कभी मॉस्को पर दबाव डालने के लिए जो एक टास्क फोर्स गठित की गई थी, उसे चुपचाप भंग कर दिया गया है। बाइडन-काल के पश्चिमी गठबंधन की एकजुटता अब बिखर चुकी है और जब पूरे विश्व का ध्यान इज़रायल-ईरान संघर्ष की ओर केंद्रित है, तो रूस को अपने लिए मौका नज़र आ रहा है।

यह क्षण केवल यूक्रेन के बारे में नहीं है। पुतिन की वाणी और कार्यवाहियाँ एक बहुत व्यापक महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं और वह है, पूर्व सोवियत क्षेत्र में रूसी दबदबे को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उदयपुर में फ्रांसीसी महिला पर्यटक के साथ दुष्कर्म

उदयपुर, 24 जून (का.सं)। पर्यटन नगरी उदयपुर को एक और घटना ने शर्मशार किया है, जिसमें एक फ्रांसीसी महिला पर्यटक के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यह घटना शहर के बड़गांव थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम घटित हुई है, जब युवती एक कैफे में पार्टी के लिए गई थी।

जानकारी के अनुसार, कैफे में उसकी मुलाकात एक स्थानीय युवक से हुई, जिसने पहले दोस्ती का नाटक किया और फिर उसे अपने किराए के मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पीड़िता खतरे से बाहर है और निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, जबकि आरोपी फरार है।

- फ्रांसीसी युवती को एक युवक कैफे में चल रही पार्टी से शहर दिखाने का झाँसा देकर अपने अपार्टमैंट में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

थानाधिकारी पूरण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि युवती और युवक की मुलाकात एक कैफे में हुई थी। पार्टी के दौरान युवक ने युवती से बातचीत की और बाहर चलकर शहर का सुंदर नजारा दिखाने का झांसा दिया। इसी बहाने वह उसे अपने अपार्टमेंट में ले गया। वहां जब युवती ने युवक के साथ गले लगने से इंकार किया तो उसने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामनेई कहाँ हैं?

जब से अमेरिका की रेड ईरान पर शुरु हुई और खत्म हो गई, अयातुल्ला की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आया है, बल्कि, विदेश मंत्री अब्बास अराघची ही ईरान का पक्ष जनता के सामने रख रहे हैं, चाहे जिनेवा हो या तेहरान या मॉस्को

- विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अयातुल्ला को जमीन के नीचे बहुत नीचे बने बंकर में, जो तेहरान से कुछ दूरी पर स्थित है, में रखा गया है।
- ट्रंप ने सदा की भाँति दम्भपूर्वक कहा, हमारी इंटैजिलैंस एजेंसी ने चिन्हित कर लिया है, अयातुल्ला कहाँ हैं और हम जब चाहे उन्हें वहाँ से पकड़ सकते हैं।
- खामनेई एक गरीब धार्मिक स्कॉलर के पुत्र हैं, जो बड़ी मेहनत से एक-एक सीढ़ी चढ़कर वहाँ पहुँचे हैं, जहाँ वे अब हैं।
- प्रारंभ से खामनेई ने सेना के वरिष्ठ उच्चाधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखे हैं, जो मजबूती से उनके साथ है और मध्यम वर्ग व प्रवासी ईरानी चाहे जितना भी खामनेई के खिलाफ हों, उनका तख्त नहीं बदल सकते।

-अंजन रॉय-
-ऑटवा (कैनडा) से-

ऑटवा (कैनडा), 24 जून। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा अचानक संघर्षविराम की घोषणा के बीच, ईरान को लेकर इस समय सबसे बड़ा रहस्य यह है कि देश के स्वयंभू सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई पूरी तरह से लापता हैं।

जब से अमेरिका के हमले शुरु और खत्म हुए, सर्वोच्च नेता की ओर से बदलती हुई स्थिति को लेकर कोई बयान नहीं आया है। इसके बजाय, जिनेवा के अंतरराष्ट्रीय होटल, तेहरान और मॉस्को की अपनी व्यस्त यात्राओं के बीच, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची ही सारी बात कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि ईरान पर अमरीकी हमले का सबसे बड़ा आलोचक मॉस्को है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के इस कदम को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए इसकी निंदा की है। हालांकि, यूक्रेन पर अपने हमले के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अमेरिका की ‘‘ट्रैवल एडवायज़री’’ भारत के लिए अपमानजनक है’

कांग्रेस ने सवाल उठाया, इस अपमान पर मोदी सरकार चुप क्यों है?

- दरअसल अमेरिका सरकार ने अमेरिकन महिलाओं को दुष्कर्म की घटनाओं का हवाला देकर अकेले भारत नहीं जाने की सलाह दी, साथ ही कहा कि अमेरिकन अधिकारी भी सरकार की अनुमति लेकर ही भारत जा सकते हैं।
- कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर, जो असल में फौजी वर्दी में आतंकवादी है, के साथ ट्रंप खाना खा रहे हैं और भारत के खिलाफ ट्रैवल एडवायज़री जारी कर रहे हैं, यह अपमानजनक है।
- कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया और कहा, मोदी ने 11 सालों में विदेशी शक्तियों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर, आज भारत के साथ कोई नहीं है। यह कैसी विदेश नीति है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जून। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को भारत यात्रा के विषय में अमेरिका द्वारा दी गई सलाह (एडवाइजरी) को लेकर मोदी सरकार की चुप्पी पर तीखा हमला किया।

उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सच्चाई यह है कि अमेरिका ने भारत के लिए लेवल-2 की यात्रा सलाह जारी की है और खासतौर पर अपनी महिलाओं को, दुष्कर्म के अनेक मामलों का हवाला देते हुये, अकेले भारत यात्रा न करने की सलाह दी है। इसके साथ ही, अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि भारत में विभिन्न प्रकार के अपराध, हिंसा की घटनाएं और आतंकवादी हमले हो सकते हैं और अमेरिकी अधिकारियों को भारत आने से पहले सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा।

श्रीनेत ने जोर देते हुये कहा कि सबसे विडंबनापूर्ण बात यह है कि इस तरह की एडवाइजरी भारत के लिए जारी की जा रही है, जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ जारी नहीं किया जा रहा है, जो एक आतंकवादी देश है। मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम जैसे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्कूल व्याख्याता-कोच भर्ती परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार

जयपुर, 24 जून। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल व्याख्याता एवं कोच स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा-2024 में दखल से इनकार करते हुए आरपीएससी को तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा कराने को मंजूरी दी है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षा कार्यक्रम को यूजीसी-नेट जून 2025 परीक्षा से टकराव के आधार पर चुनौती देने वाली एसएलपी भी निस्तारित कर दी है। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने ये आदेश मामले में दायर 17 विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

- ये परीक्षाएँ आरपीएससी के तय कार्यक्रम के अनुसार होंगी।

एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि इस भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम यूजीसी की 25 जून से 29 जून 2025 तक होने वाली नेट परीक्षा से टकरा रहा है। ऐसे में परीक्षा कार्यक्रम को पुनः निर्धारित किया जाए। एसएलपी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘संस्कृत को करोड़ों रूपए और दक्षिण भारतीय भाषाओं को घड़ियाली आँसू’

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर भाषा के मुद्दे पर मोदी सरकार की तीखी आलोचना की

- स्टालिन ने कहा कि मोदी ने तमिलनाडु दौरे पर और यहाँ तक कि युनाइटेड नेशनल में भी कहा कि, तमिल प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, पर वास्तव में केन्द्र सरकार का तमिल भाषा के प्रति रूख पक्षपातपूर्ण है।
- स्टालिन ने आरोप लगाया कि मदूरै के कीलडी गाँव में यह भी उत्खनन और लोहे के उद्गम से संबंधित रिपोर्ट को केन्द्र सरकार नकार रही है। स्टालिन ने कहा कि रिपोर्ट से स्पष्ट है कि लौह युग का उद्गम तमिलनाडु में हुआ था, पर, केन्द्र सरकार इस पर प्रश्नचिन्ह लगा रही है।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जून। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज भाषा के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला तथा कहा कि सरकार संस्कृत के लिए धनराशि आवंटन में उदारता बरत रही है और तमिल तथा अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए कृपणता से काम ले रही है। वित्तीय आवंटन के अंतर से भाजपा का घोर पक्षपात उजागर हो गया है।

स्टालिन यहीं नहीं रूके। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह तमिल की समृद्ध विरासत एवं प्राचीन धरोहर को नष्ट एवं समाप्त करने की निरन्तर कोशिश करती आ रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तमिल, जिन्हें अपना स्वाभिमान सर्वाधिक प्रिय है, अपने राज्य को कभी दिल्ली से शासित नहीं होने देंगे।

मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि ‘‘संस्कृत को करोड़ों मिलते हैं और दक्षिण भारतीय भाषाओं को घड़ियाली आँसुओं के अलावा कुछ नहीं मिलता।’’ उन्होंने मोदी सरकार पर कीलडी की खुदाई रिपोर्ट और लोहे की प्राचीनता संबंधी रिपोर्ट को जानबूझकर अमान्य करने का आरोप लगाया, जो यह घोषणा करती है कि लोहे का युग तमिलनाडु से शुरू हुआ था।

उन्होंने एक्स पर लिखा, सारा पैसा संस्कृत के लिए है, तमिल के लिए प्यार का झूठा दिखावा है। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें संस्कृत के लिए भारी वित्तीय मदद का उल्लेख है, जबकि तमिल और अन्य दक्षिणी भाषाओं और उड़िया, जो कि प्राचीन एवं शास्त्रीय भाषाएं हैं, के लिए वित्तीय आवंटन नगण्य है।

तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, जबकि संस्कृत को यह दर्जा इसके एक साल बाद 2005 में दिया गया था। इसके बाद कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया ने भी इस प्रतिष्ठित वर्ग में स्थान पाया। लेकिन इन भाषाओं के विकास के लिए आवंटन से स्पष्ट रूप से संस्कृत के पक्ष में झुकाव साफ दिखाई देता है, क्योंकि संस्कृत को अधिकतम राशि मिली है।

संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए, केन्द्र सरकार ने 2014-15 से 2024-25 तक के दस वर्षों में 2532.59 करोड़ रूपये खर्च किए, जो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लालू निर्विरोध राजद अध्यक्ष निर्वाचित

पटना, 24 जून। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 13वीं बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है।

राजद के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी रामचंद्र पूर्वे ने मंगलवार को पटना में संवाददाताओं को बताया कि अध्यक्ष पद के लिए यादव ही एकमात्र उम्मीदवार थे और नामांकन वापसी की

- लालू प्रसाद यादव 13वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष चुने गए हैं।

निर्धारित 15 घंटे की समय-सीमा के भीतर किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। इसके साथ ही, उनकी निर्विरोध ताजपोशी की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

पूर्वे ने कहा कि यादव को निर्वाचन का आधिकारिक प्रमाण पत्र 05 जुलाई को पटना में आयोजित होने वाली पार्टी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या इज़रायल अपनी बमबारी तेहरान के सुबह चार बजे बंद कर देगा?

क्या, ईरान भी इस बमबारी बंद होने के एवज़ में अपनी तरफ से ‘‘मिसाइल दागना’’ बंद कर देगा?

- इन दोनों सवालों का मुकम्मिल जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए ट्रंप द्वारा बड़े शोर-शराबे से ईरान-इज़रायल युद्ध में ‘‘सीज़फायर’’ की घोषणा, तूफान में एक टिमटिमाते दीये की भाँति है, कभी जलता है और कभी बुझने के कगार पर आ जाता है। अतः कुछ भी पूर्ण विश्वास से कहना मुमकिन नहीं हैं।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जून। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की कि ईरान और इज़रायल के बीच पूर्ण और संपूर्ण संघर्षविराम पर सहमति बन गई है, जिसके अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावी होने की उम्मीद है।

ईरान और इज़रायल ने सुबह सीज़फायर की पृथक-पृथक घोषणा की, ट्रंप ने संधि का ब्यौरा दिया, जिसने 12 दिन से चल रहे युद्ध को रोक दिया है।

हालांकि, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन यह भी कहा कि अगर इज़रायल तेहरान समय के अनुसार सुबह 4 बजे तक हमले रोक देता है, तो ईरान उसके बाद कोई प्रतिक्रिया जारी रखने का इरादा नहीं रखता।

सूत्रों के अनुसार, ईरान ने खाड़ी देशों के माध्यम से अमेरिका से इज़रायल पर संघर्ष विराम के लिए दबाव डालने की मांग की है।

तेहरान ने क़तर, सऊदी अरब और ओमान से आग्रह किया है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से इज़रायल पर तत्काल संघर्ष विराम के लिए दबाव डालने को कहें। बदले में, ईरान परमाणु वार्ताओं में लचीलापन दिखाने को तैयार हो सकता है। यह जानकारी रॉयटर्स को दो ईरानी और तीन क्षेत्रीय सूत्रों ने दी।

खाड़ी देशों के नेता और उनके शीर्ष राजनयिक पूरे सप्ताहांत फोन पर सक्रिय रहे, वे एक-दूसरे से, तेहरान से, वॉशिंगटन से और अन्य पक्षों से बात कर रहे थे, ताकि ईरान और इज़रायल के बीच अब तक के सबसे बड़े टकराव को और अधिक बढ़ने से रोका जा सके।

ईरान का रुख स्पष्ट है कि जब तक इज़रायल बमबारी नहीं रोकता, ईरान पूर्ण संघर्ष विराम स्वीकार नहीं करेगा। ईरान ने खाड़ी देशों के माध्यम से यह संकेत दिया है कि वह हमले तभी रोकेगा जब इज़रायल हमले रोकेगा। और इसके बाद वह परमाणु वार्ताओं को फिर से शुरू कर सकता है।

ट्रंप की घोषणा के बाद भी दोनों पक्षों ने मिसाइल हमलों की रिपोर्ट दी। इज़रायल का दावा है कि उसने ईरान से दागी गई मिसाइलों को रोका है, जबकि ईरान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करने से इनकार किया है।

इज़रायल ने अभी तक संघर्ष विराम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और यह कहा है कि यदि ईरान फिर से हमला करता है, तो वह ज़ोरदार जवाब देगा।

राजनयिक स्तर पर, ईरान और यूरोपीय देशों, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ताएं 20 जून को जेनेवा में शुरू हुई हैं। ये वार्ताएं संघर्ष विराम से अलग हैं, और ईरान का कहना है कि वह उस समय तक कोई भी बातचीत नहीं करेगा जब तक उस पर हमला हो रहा है।

निचोड़ यह है कि अमेरिका ने एकतरफा संघर्ष विराम की घोषणा की है, लेकिन ईरान ने किसी औपचारिक समझौते से इनकार किया है, और इज़रायल भी सतर्क बना हुआ है।

संघर्ष विराम का पालन सशर्त है, इज़रायल को पहले हमले रोकने होंगे, तभी ईरान अपनी प्रतिक्रिया रोकने को तैयार है।

राजनयिक प्रयास जारी हैं, जेनेवा में यूरोपीय देशों की मध्यस्थता में परमाणु मुद्दों पर बातचीत प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन संघर्ष विराम और परमाणु वार्ताएं फिलहाल एक-दूसरे से अलग हैं।

अब देखने वाली बातें ये होंगी, क्या इज़रायल तेहरान समय अनुसार सुबह 4 बजे तक अपने हमले रोक देगा? क्या ईरान बदले में मिसाइल हमले रोक देगा? और क्या जेनेवा में चल रही वार्ताएं परमाणु कूटनीति और सैन्य तनाव को जोड़ने में सफल होंगी?

महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रियों को आइपैड दिए

मुंबई, 24 जून। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने ‘कागज रहित’ प्रशासन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपने सभी मंत्रियों को ‘आईपैड’ उपलब्ध करा दिया है, ताकि वे अपने नियमित आधिकारिक कार्य कुशलतापूर्वक कर सकें।

राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार, मंत्रियों को राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी

- कागज़ रहित कामकाज को प्रोत्साहन देने के लिए यह कदम उठाया गया है।

विभाग द्वारा आईपैड का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के बारे में जानकारी दी गई और प्रत्येक मंत्री को डिवाइस और उनके आधिकारिक ईमेल खातों के पासवर्ड सहित लॉगिन आईडी भी दिए गए।

सूत्रों ने बताया कि अब कैबिनेट एजेंडा, नोट्स और पिछली बैठकों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK